जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 316 प्रभात जालोर, शुक्रवार 21 फरवरी, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

# यूक्रेन युद्ध का ''अन्त'' क्या कोरिया वॉर (1950-53) की तरह होगा?

## कोरियन वॉर में केवल दीर्घकालीन ''सीज़फायर'' हुई थी, कोई अधिकृत शान्ति स्थापित करने वाली संधि नहीं हुई है। जिसका अर्थ है, युद्ध की स्थिति अनिर्णित है तथा समय-समय पर स्थिति में उफान आ सकता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- इस कोरियन स्टाइल समाधान का व्यवहारिक अर्थ है, किसी भी पार्टी को अपनी ओर से खास ''कन्सैशन'' (रियायत) नहीं देनी पड़ती।
- यूक्रेन के संदर्भ में इसका मतलब है कि यूक्रेन व रूस एक लम्बे समय तक रहने वाली ''सीज़फायर'' पर सहमत हो जाते हैं तथा दोनों देशों के बीच सीमा पर भारी संख्या में सैना तैनात रहेगी, अपने हथियारों व मशीनों सहित।
- यूक्रेन की सार्वभौमिकता बरकरार रहेगी तथा रूस के कब्जे में गये क्षेत्र पर यूक्रेन का नियंत्रण नहीं रहेगा।
- ट्रम्प पूरे जोर-शोर से लगे हैं, यूक्रेन वॉर का ऐसा ''समाधान'' ढूंढ़ने में। अगर ट्रम्प अपने इस प्रयास में सफल होते हैं तो समस्याओं का तुरन्त, आनन-फानन, किसी भी तरह ''समाधान'' निकाल लेने की उनकी छवि को मजबूती मिलेगी, अमेरिका में और बाहर विदेशों में।

नई दिल्ली, 20 फरवरी। अपने कार्यकाल के एक महीने के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प स्वयं को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने शेखी बघारा थी कि पद संभालने के बाद 24 घंटों में वो यूक्रेन युद्ध समाप्त करवा देंगे। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक डील करने के लिए अत्यधिक जल्दी में हैं, जैसा कि उनकी हाल की बयानबाजी और सऊदी अरब में चल रही गोपनीय अमेरिकी-रूसी वार्ताओं से संकेत मिलता है।

ऐसी क्या बात है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैंस्की और उनके यूरोपीय सहयोगियों को शामिल किए बिना, डील करने के लिए ट्रंप को प्रेरित कर रही है? विश्लेषकों का कहना है कि कई कारक हैं जो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं।

ट्रंप ''डील-मेकर'' के रूप में अपनी छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा खुद को एक ''मस्टर निगोशिएटर'' के रूप में प्रस्तुत किया है, और यूक्रेन युद्ध का जल्द समाधान करने से उनकी प्रतिष्ठा में मजबूती आएगी।

उन्होंने लगातार अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सहायता और सैन्य हस्तक्षेपों की आलोचना की है, यह तर्क देते हुए कि यूक्रेन को समर्थन देना एक वित्तीय बोझ है। समझौता करवाकर, वो दावा कर सकते हैं कि उन्होंने अमेरिकी करदाताओं के पैसे की बचत की है और ऐसा करके वो संसाधनों को फिर से अपने देश में लगा सकते हैं। ट्रंप के समर्थकों का एक भाग विदेशी संघर्षों से पीछे हटने के पक्ष में है, और यूक्रेन में अमेरिकी भागीदारी को अनावश्यक मानता है। अपनी शर्तों पर युद्ध को समाप्त करवाना ट्रंप के इस जनाधार को खुश कर सकता है।

ट्रंप द्वारा बार-बार किए जा रहे इन दावों में, कि युद्ध के लिए यूक्रेन भी जिम्मेदार है, रूस का प्रपोगैंडा नज़र आता है। नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के प्रति उनका सार्वजनिक संदेह यह संकेत देता है कि वह इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को कम करना चाहते हैं, शायद यूक्रेन को बलि का बकरा बनाकर।

रूस के साथ रिश्तों को स्थिर करना वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, विशेष रूप से ऊर्जा बाजारों में, को कम करने में मदद कर सकता है, जो अमेरिकी उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। समझौता करने के लिए रुस पर लगे प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करना होगा तथा रुसी एनर्जी एक्सपोर्ट सुनिश्चित करना पड़ेगा।

ट्रंप का पुतिन के साथ एक जटिल संबंध रहा है। वे रूस के साथ समझौते को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जिससे रिश्तों की फिर से नई शुरुआत की जा सके, संभवतः अमेरिकी व्यापार हितों के लिए कुछ रियायतों के बदले में।

इन कारकों के बावजूद, एक ऐसा समझौता जो रुस को भारी फायदा पहुंचाता हो, को कांग्रेस, नाटो सहयोगियों और यहां तक कि ट्रंप के अपने प्रशासन से भी विरोध का सामना करना पड सकता है। खतरा यह है कि जल्दबाजी में किया गया कोई समझौता

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## सोनिया गांधी की तबियत बिगड़ी, सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती

नई दिल्ला, 20 फरवरी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई, उनको सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक

- अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है तथा सेहत में सुधार बताया जा रहा है।

टीम उनकी निगरानी कर रही है और उनकी तबीयत अब ठीक है। शुक्रवार को उनको छुट्टी मिलने की संभावना है।

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## राज्य सरकार एसआई प्रकरण में शुक्रवार को पक्ष रखे

जयपुर, 20 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर

- अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया था कि भर्ती रद्द करने के मामले में राज्य सरकार का निर्णय चार महीने में कर लिया जायेगा।

लीक मामले में राज्य सरकार को अपना

( शेष पृष्ठ 3 पर )

# 'गत दशकों में ''यूएस एड'' ने भारत में किस-किस सरकार व गैर सरकारी संस्थाओं को पैसे दिये?'

## इस मुद्दे पर मोदी सरकार जाँच करके एक ''श्वेत पत्र'' जारी करे- कांग्रेस ने माँग की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- जैसा कि विदित ही है, ट्रम्प ने भारत को ''वोटर टर्न आउट'' बढ़ाने के लिए दिये गये 21 मिलियन डॉलर के अनुदान की बात करते हुए, यह भी कहा है कि भारत को ऐसे अनुदान की कोई जरूरत नहीं, पर, शायद जिन्हें यह अनुदान राशि प्राप्त हुई, वे किसी ''व्यक्ति विशेष'' को जिता कर लाना चाहते थे।
- कांग्रेस के राष्ट्रपति ट्रम्प के इन उद्‌गारों को बेबुनियाद व फिजूल बताया और कहा, श्वेत पत्र जारी करके ही इस कुप्रचार का अंत हो सकता है।
- ऐसे ही मद के तहत यूएस एड ने 29 मिलियन डॉलर बाँग्लादेश तथा 39 मिलियन डॉलर नेपाल को भी अनुदान के रूप में दिये थे।

नई दिल्ली, 20 फरवरी। यू.एस.एड द्वारा भारत के चुनावों में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद पर सत्तारुढ़ पार्टी भाजपा और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो अंतहीन सिलसिला चल निकला, उसके बीच एक सकारात्मक कदम उठाते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है यू.एस. एड द्वारा भारत में कई दशकों से सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को दी जा रही मदद पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के दावे को बेतुका करार दिया।

ट्रम्प ने कहा था कि ''हम भारत में वोटर टर्न आउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन डॉलर क्यों दें? मुझे लगता है वे किसी और को निर्वाचित करवाने का प्रयास कर रहे थे।''

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इन दिनों यू.एस. एड बहुत चर्चा में है इसकी स्थापना 3 नवम्बर 1961 को की गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वे कहने के लिए तो कम से कम बेतुके हैं।

उन्होंने लिखा, भारत सरकार को जल्द से जल्द एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जिसने दशकों से यू.एस.एड द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण हो।

अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाले विभाग ''गवर्नमैंट एफिशिएंसी'' ने 16 फरवरी को उन मदों की लिस्ट घोषित थी जिसमें अमेरिकन कर दाता को पैसा खर्च किया जा रहा है इसमें भारत में वोटर टर्न आउट के लिए दिए जा रहे 21 मिलियन डॉलर का भी जिक्र था।

विभाग ने समस्त सहायता रोकने की घोषणा की। इसमें बांग्लादेश को पॉलिटिकल लैंड स्केप के विस्तार के लिए 29 मिलियन डॉलर, वित्तीय संघवाद के लिए 20 मिलियन डॉलर नेपाल को जैवविविधता के संरक्षण के लिए दी जा रही 19 मिलियन डॉलर की सहायता शामिल है।

ट्रम्प ने बुधवार को इस पर कहा था ''हम भारत को 21 मिलियन डॉलर क्यों दे रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है भारत हम पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है और इस वजह से हम भारत के व्यापारिक क्षेत्र में घुस नहीं पाते हैं।''

# 'दिल्ली के नये मंत्रिमंडल में 71 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ ''क्रिमिनल केस'' चल रहे हैं'

## एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ए.डी.आर.) ने मंत्रियों द्वारा चुनाव से पूर्व शपथ पत्र द्वारा दायर जानकारी के आधार पर यह जानकारी सार्वजनिक की है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- ए.डी.आर. ने यह भी जानकारी दी है कि मंत्रियों में 29 प्रतिशत मंत्री अरबपति हैं।

नई दिल्ली, 20 फरवरी। दिल्ली के 7 नए मंत्रियों में से 5 ने अपने खिलाफ क्रिमिनल केस होने की घोषणा की है, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। नव-निर्वाचित विधायकों में से दो अरबपति हैं। यह जानकारी दी है, चुनाव अधिकारों (ए.डी.आर.) से जुड़े संगठन एसोएिशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने।

यह जानकारी चुनाव से पूर्व इन मंत्रियों द्वारा दायर सत्यापित शपथ पत्र में घोषित की गई है।

ए.डी.आर. के विश्लेषण के अनुसार, 7 में से 5 मंत्रियों (71 प्रतिशत) के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि दो (यानि 29 प्रतिशत) अरबपति है।

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ भी अपराधिक मामले हैं।

एक मंत्री आशीष सूद के खिलाफ तो गंभीर किस्म के अपराधिक मामले दर्ज हैं।

आर्थिक मोर्चे पर देखे तो 2 मंत्री अरबपति हैं, पहले है मनजिंदर सिंह सिरसा जो सबसे अमीर हैं। राजौरी गार्डन से चुनाव जीत कर विधायक बने मनजिंदर सिंह 248.85 करोड़ रूपए की सम्पत्ति के मालिक हैं। सबसे कम सम्पत्ति करावाल नगर के विधायक कपिल मिश्रा की है।

उन्होंने 1.06 करोड़ रूपए की सम्पत्ति घोषित की है।

सातों मंत्रियों की औसत सम्पत्ति का औसत 56.0 करोड़ रूपए है। सभी ने अपनी देनदारियां भी घोषित की हैं, सर्वाधिक देनदारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर 74.36 करोड़ रूपए की है।

सभी मंत्रियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बताई है। इनके 6 मंत्री स्नातक या उससे अधिक शिक्षित है, एक मंत्री बारहवीं पास है।

5 मंत्रियों की उम्र 41 से 50 के बीच है। वही दो की 51 से 60 के बीच। कैबिनेट में एक ही महिला है और वो मुख्यमंत्री हैं।

अपराध और भ्रष्टाचार को अब सामान्य बात की तरह स्वीकार कर लिया गया है। एक समय तक जब आर.एस.एस. उच्च नैतिक आदर्शों और चरित्र का निर्माण का दम भरती थी और भाजपा को ''पार्टी विद डिफरैंस'' का तमगा दिया गया था। एक वरिष्ठ आर.एस.एस. नेता ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि सत्ता ने सब कुछ बदल दिया है।

## चार विधायकों ने विधानसभा में लगे आईपैड तोड़े

जयपुर, 20 फरवरी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने विधायकों को सदन में लगाए गए आईपैड का सही तरीके से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। स्पीकर ने कहा कि, विधायक आईपैड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो इसका स्टैंड की तरह यूज़ करते हैं, इस पर दबाव देते हैं। चार विधायकों के आईपैड टूट चुके हैं, जो

- स्पीकर देवनानी ने नाराज़गी प्रकट की कि कुछ विधायक इसका इस्तेमाल स्टैण्ड की तरह कर रहे हैं।

मुझे रिपेयर करवाने पड़े हैं। देवनानी ने कहा कि इन चारों के नाम भी मेरे पास हैं। कुछ विधायक इसे लॉक करके जाते हैं, कोई भी इसको लॉक करके नहीं जाए। कुछ विधायक आईपैड को निकालकर फोन चार्ज करने लग जाते हैं। यह फोन कनेक्टर नहीं है। मुझे सदन में बार-बार ये बातें दोहरानी पड़ेगी तो ठीक नहीं है। आईपैड लगाने पर 16 से 17 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका घर की चीज की तरह इस्तेमाल करें।

# डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप नहीं हुआ- मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म

## राज्य सरकार ने फोन टैपिंग प्रकरण पर विधानसभा में जवाब दिया

- विधानसभा संवाददाता -

- नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, यदि सरकार यह जवाब उसी दिन दे देती तो बात वहीं खत्म हो जाती। भाजपा के ही कई लोग नहीं चाहते थे कि सीएम का जवाब ढंग से हो।
- गृह राज्य मंत्री बेढ़म ने कहा कि किरोड़ी मीणा सार्वजनिकरूप से यह कह चुके हैं कि उनका फोन टैप नहीं हुआ है।

जयपुर, 20 फरवरी। विधानसभा में गुरुवार को राज्य सरकार ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों का जवाब दिया। परन्तु इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सदन में कहा कि किरोड़ी लाल मीणा सहित किसी का फोन टैप नहीं हुआ। मंत्री के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- जब सरकार ने कहा कि किरोड़ी का फोन टैप नहीं किया तो फिर आप उनके आरोपों पर क्या कार्रवाई करेंगे। फिर किरोड़ी का इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार करते?

नेता प्रतिपक्ष ने जब सवाल उठाए तो वन मंत्री संजय शर्मा ने पोस्टर लहरा दिया। इस पर जूली ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मंत्री ही पोस्टर लहरा रहे हैं, यह किस नियम में है। इस पर कुछ देर के लिए हंगामा हुआ।

जूली ने कहा- मंत्री ने आज जो जवाब दिया, वो उसी दिन दे देते तो बात ही खत्म हो जाती। भाजपा के ही कई लोग नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जवाब ढंग से हो।

बेढम ने कहा कि कुछ दिन पहले मीडिया में मंत्री किरोड़ी लाल का बयान सामने आया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका मोबाइल फोन सर्विलांस पर रखा गया। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। जबकि किरोड़ी मीणा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन कर चुके हैं। मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार ने किरोड़ी लाल का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, आपके जवाब से हम संतुष्ट हैं। आपके कैबिनेट मंत्री ने आप पर आरोप लगाया और आप कह रहे हैं फोन टैप नहीं करवाया जा रहा। अब आप उन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं।

जूली ने आगे कहा कि दो बातें नहीं हो सकतीं। वो कह रहे हैं कि फोन टैप हो रहा है। आपके प्रदेशाध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया है। उन्होंने (किरोड़ी ने) नोटिस के जवाब में में यह नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा है। उन्होंने यह कहा है कि उन्हें यह बातें सार्वजनिक स्तर पर नहीं करनी चाहिए थीं।

जूली ने कहा कि- गृह राज्य मंत्री मीडिया में जवाब देते हैं कि फोन टैप नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज से

( शेष पृष्ठ 3 पर )